



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2010/आषाढ़ 24, 1932

No. 1425]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2010/ASADHA 24, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2010

का.आ. 1678(अ).— अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद 1959 (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाए ।
(2) ये नियम पहली जनवरी, 2006 से लागू हुए समझे जाएंगे ।
2. अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में "अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद नियम" शब्द रखे जाएंगे ।
3. मूल नियम 6 में :-
(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) ऐसा व्यक्ति जो 1 जनवरी, 2006 से पहले पूर्णकालिक निर्धारक के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है, को तारीख 11 नवम्बर, 2008 के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के का०ज्ञा०सं० 3/13/2008-स्था० (वेतन-11) के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञेय रूप में ऐसा वेतन दिया जाएगा, परंतु यह कि ऐसा वेतन पद के

वेतनमान या 80,000 रु०, इसमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा और वह ऐसे भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जो सेवारत सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है ।

(4क) ऐसा व्यक्ति जो 1 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् से पूर्णकालिक निर्धारक के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है, को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो उसकी पेंशन और पेंशन के समतुल्य या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को मिलाकर उसके द्वारा सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त किए गए अंतिम वेतनमान या 80,000 रु०, इसमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा और वह ऐसे भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जो सेवारत सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है ।

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) ऐसा व्यक्ति जो सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक नहीं है तथा अधिकरण द्वारा पूर्णकालिक निर्धारक के रूप में नियुक्त किया गया है, को, यथास्थिति, ऐसा वेतन दिया जाएगा जो उसकी हैसियत, अनुभव और अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए अवधारण किया गया हो, परंतु यह कि ऐसा वेतन पद के वेतनमान या 80,000 रु०, इसमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो ऐसे वेतन पर प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है ।"

4. मूल नियम के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, जैसा भी अवधारण हो, ऐसे शर्तों और निबंधनों पर अधिकरण के लिए समूह 'क' अधिकारियों को नियुक्त करेगी ।

(7क) अधिकरण का अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसे शर्तों और निबंधनों पर अधिकरण के लिए समूह 'क' अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों को नियुक्त करेगा ।"

[फा. सं. 1/6/98-बीएम]

यू. एन. पंजियार, सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

छटे वेतन आयोग की सिफारिशें जो 01.01.2006 से प्रवृत्त हुई हैं, के आधार पर इन नियमों को संशोधित किया गया है, यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2010

S.O. 1678(E).—In exercise of the power conferred by section 13 of the Inter-State River Water Disputes Act-1956 (33 of 1956), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the Inter- State Water Disputes Rules, 1959 , namely:-

1. (1) These rules may be called the Inter-State Water Disputes, 1959 (Amendment) Rules, 2010.
(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of January, 2006.
2. In the Inter State Water Disputes Rules, 1959 (hereinafter referred to as the principal rules), for the words “ Inter-State Water Disputes Rules”, the words “Inter-State River Water Disputes Rules” shall be substituted.
3. In rule 6 of the principal rules, -
(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) A person, being a retired Government servant appointed as a whole-time Assessor, before 1 January, 2006 shall be paid such salary as admissible in terms of Ministry of Personnel, P.G. and Pension (Deptt. of Personnel and Training) O.M.No.3/13/2008-Estt.(Pay-II) dated the 11th November 2008, provided that such salary shall not exceed maximum of the scale of pay of the post or Rs.80000/- whichever is less; and he shall be entitled to draw such allowances and other benefits as are admissible to a serving Government servant.

(4A) A person, being a retired Government servant appointed as a whole-time Assessor, on or after 1st January 2006 shall be paid such salary as which, together with his pension and pension equivalent or any other form of retirement benefit which shall not exceed the last pay drawn by him before retirement or Rs. 80000/- whichever is less and shall be entitled to draw such allowances and other benefits as are admissible to a serving Government Servant.

-
-
- (b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) A person, not being a serving or a retired Government servant appointed as a whole-time Assessor by a Tribunal, shall be paid such salary as may be determined keeping in view his status, experience and qualifications provided that such salary, shall not be more than the

maximum of the scale of pay of the post or Rs.80000/-, whichever is less and he shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government servant of the first grade on such a pay.”;

4. For the rule 7 of the principal rules, the following shall be substituted, namely:-

“(7) The Central Government may, in consultation, with the Chairman of the Tribunal, appoint group 'A' officers for the Tribunal, on such terms and conditions as it may determine.

(7A) The Chairman of the Tribunal may appoint Officers other than Group 'A' officer for the Tribunal on such terms and conditions as determined by the Central Government.”

[F. No. 1/6/98-BM]

U. N. PANJIAR, Secy.

Explanatory Memorandum

Since these rules are amended on the basis of recommendations of the Sixth Pay Commission which came into force w.e.f. 1.1.2006, it is certified that no person is likely to be adversely effected by this notification being given retrospective effect.